



12 मिनट	8	14	1	GS2 • 9	GS3 • 13
पढ़ने का समय	मुख्य खबरें	संक्षेप में	मेन्स प्रश्न	पेपर मिश्रण	

01 — आज 2 मिनट में

5 खबरें जो छोड़नी नहीं हैं

1 डिफेंस सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, DAC ने 1.10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी

क्यों ज़रूरी: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के सैन्य खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

2 सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश आसान, Sebi ने FPIs को दी बड़ी राहत

क्यों ज़रूरी: SEBI ने एक परिपत्र जारी कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की स्थिति में निवेशक समूह का विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी है।

GS3 • अर्थव्यवस्था

P

3 गाज़ा में नरसंहार का "संभावित खतरा", इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की चेतावनी

क्यों ज़रूरी: इज़राइल द्वारा लगाए गए नाकेबंदी और बुनियादी ढांचे के विनाश के आरोपों के बीच, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गाज़ा में नरसंहार के 'संभावित जोखिम' के प्रति चेतावनी दी है।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

M

4 दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरी, 7 छात्रों की मौत

क्यों ज़रूरी: सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने से सात छात्रों की मृत्यु होने के उपरांत, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नगर निगम दिल्ली (MCD) को PG छात्रावासों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

GS2 • राज्यव्यवस्था एवं संविधान

P

M

5 BRICS देशों के बीच जॉइंट स्टेटमेंट पर समझौता होने के करीब

क्यों ज़रूरी: BRICS वार्ताकार भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन से पूर्व, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों के बावजूद साझा प्राथमिकताओं पर आम सहमति बनाने हेतु एक संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दे रहे हैं।

GS2 • अंतर्राष्ट्रीय संबंध

P

GS3 · विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

P

M

डिफेंस सेक्टर को मिलेगा बूस्ट, DAC ने 1.10 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी

चर्चा में क्यों: रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के सैन्य खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

याद रखें

- Defence Acquisition Council (DAC): भारत में सैन्य खरीद को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था।
- राजनाथ सिंह: Defence Acquisition Council (DAC) के अध्यक्ष।
- खरीद मूल्य: सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए Rs 1.10 लाख करोड़ स्वीकृत।

मेन्स कोण रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति में 'अनिवार्यता की स्वीकृति' (Acceptance of Necessity) के महत्व और रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/118759

GS2 · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

M

गाज़ा में नरसंहार का "संभावित खतरा", इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की चेतावनी

चर्चा में क्यों: इज़राइल द्वारा लगाए गए नाकेबंदी और बुनियादी ढांचे के विनाश के आरोपों के बीच, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने गाज़ा में नरसंहार के 'संभावित जोखिम' के प्रति चेतावनी दी है।

याद रखें

- ICJ ने इसके होने पर अंतिम निर्णय दिए बिना नरसंहार के 'संभावित जोखिम' (plausible risk) की चेतावनी दी।
- AI-assisted targeting: बुनियादी ढांचे के विनाश और सामूहिक हत्या के आरोपों में एक कारक के रूप में पहचाना गया।

मेन्स कोण नरसंहार के आरोपों को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक निकायों की भूमिका और सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने की चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/118736

GS3 · अर्थव्यवस्था

P

सरकारी सिक्क्योरिटीज में निवेश आसान, Sebi ने FPIs को दी बड़ी राहत

चर्चा में क्यों: SEBI ने एक परिपत्र जारी कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की स्थिति में निवेशक समूह का विवरण प्रस्तुत करने से छूट दी है।

याद रखें

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने जून में सरकारी प्रतिभूतियों में FPI निवेश के लिए एकाग्रता सीमा (concentration limits) को वापस ले लिया।
- यह छूट विशेष रूप से केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले FPIs पर लागू होती है।
- डिपॉजिटरीज़ और कस्टोडियनज़ को नए निर्देश के अनुरूप अपने सिस्टम को अपडेट करना आवश्यक है।

मेन्स कोण सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए निवेश मानदंडों में ढील देने से भारत के राजकोषीय प्रबंधन और पूंजी बाजार की तरलता पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/118737

GS2 · राजव्यवस्था एवं संविधान

P

M

दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरी, 7 छात्रों की मौत

चर्चा में क्यों: सत्य निकेतन में एक इमारत ढहने से सात छात्रों की मृत्यु होने के उपरांत, दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने नगर निगम दिल्ली (MCD) को PG छात्रावासों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।

याद रखें

- सत्य निकेतन भवन ढहने से सात छात्रों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए।
- बिना लाइसेंस के PG चलाने के लिए हरिराम गुप्ता (82), उर्मिला गुप्ता (75) और महेश गुप्ता (52) को गिरफ्तार किया गया।
- सत्य निकेतन दिल्ली का एक स्थानीय क्षेत्र है जो छात्र आवास के लिए जाना जाता है।

मेन्स कोण शहरी केंद्रों में निजी पीजी (PG) आवासों के प्रबंधन में आने वाली विनियामक चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और संरचनात्मक सुरक्षा एवं छात्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपायों का सुझाव दीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/118733

BRICS देशों के बीच जॉइंट स्टेटमेंट पर समझौता होने के करीब

चर्चा में क्यों: BRICS वार्ताकार भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन से पूर्व, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों के बावजूद साझा प्राथमिकताओं पर आम सहमति बनाने हेतु एक संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दे रहे हैं।

याद रखें

- BRICS: राष्ट्रों का एक समूह जो वर्तमान में भारत में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए एक संयुक्त वक्तव्य पर बातचीत कर रहा है।

मेन्स कोण बहुध्रुवीय सहयोग के एक मंच के रूप में ब्रिक्स (BRICS) के महत्व और भिन्न अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखने वाले राष्ट्रों के बीच आम सहमति प्राप्त करने की चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/118767

ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी गिरावट, सेबी अब डेरिवेटिव्स सेटलमेंट का तरीका बदलेगा

चर्चा में क्यों: व्यापार की मात्रा में महत्वपूर्ण गिरावट और बाजार के प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के उपरांत, SEBI ने डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए निपटान मूल्य पद्धति (settlement price methodology) की समीक्षा करने की योजना की घोषणा की है।

याद रखें

- NSE का अगस्त टर्नओवर: Rs 34.48 लाख करोड़।
- BSE का अगस्त टर्नओवर: Rs 32.2 लाख करोड़।
- SEBI: Securities and Exchange Board of India।

मेन्स कोण भारत के इक्विटी डेरिवेटिव्स खंड में बाजार की अखंडता और तरलता बनाए रखने में 'सेटलमेंट प्राइस' (निर्णय मूल्य) तंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/118676

NSE के IPO से आएंगे 30,000 करोड़ रुपये, IFCI के शेयरों में उछाल

चर्चा में क्यों: SEBI ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के IPO के लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।

याद रखें

- SEBI: वह नियामक संस्था जिसने NSE के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी।
- NSE IPO: 14.89 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों की बिक्री के माध्यम से लगभग 30,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है।
- IFCI-SHCIL-NSE संबंध: IFCI के पास SHCIL की >50% हिस्सेदारी है; SHCIL के पास NSE में >4% की हिस्सेदारी है।

मेन्स कोण भारत में पूंजी बाजार की तरलता को गहरा करने में बड़े पैमाने पर होने वाले प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) के महत्व और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/118672

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) के तीन खंडों को समर्पित करने और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं

चर्चा में क्यों: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी समर्पित माल गलियारा (WDFC) के तीन खंडों को समर्पित करने और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF) 2026 का उद्घाटन करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर हैं।

याद रखें

- WDFC: माल ढुलाई के लिए समर्पित 326 किमी के तीन खंड।
- WDFC: तीनों खंडों के लिए परियोजना लागत 20,700 करोड़ रुपये है।
- गुजरात और महाराष्ट्र: WDFC खंडों और GFF 2026 की मेजबानी करने वाले राज्य।

मेन्स कोण समर्पित माल गलियारों (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) के विकास और फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना किस प्रकार भारत के वैश्विक विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था केंद्र बनने के लक्ष्य में योगदान देते हैं, चर्चा कीजिए।

पूरा नोट → satyadheesh.in/news/118654

GS2 · राजव्यवस्था · शासन · सामाजिक न्याय · अंतर्राष्ट्रीय संबंध

मणिपुर में 1,32,456 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए

मेडिकल एग्जाम पेपर लीक से 2 मिलियन छात्र दोबारा देंगे टेस्ट, मंत्री ने इस्तीफा दिया

पेरिस में स्वामीनारायण मंदिर के उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी ने दिया वर्चुअल संबोधन

महाराष्ट्र में भर्ती परीक्षाओं में सुधार के लिए 7 सदस्यीय पैनल गठित

लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की बेंच शुरू

भारत में कैश ट्रांसफर स्कीम पर खर्च होंगे 18 बिलियन डॉलर

GS3 · अर्थव्यवस्था · विज्ञान-तकनीक · पर्यावरण · सुरक्षा

अरावली हिल्स रिपोर्ट के लिए 6 महीने की मोहलत खारिज, 30 नवंबर तक की डेडलाइन

टाइगर वर्म्स से नहीं खत्म होंगे एस्केरिस के अंडे, सेहत के लिए खतरा

स्मार्ट गैस मीटर लगाने के लिए PNGRB और EESL ने साइन किया MoU

RBI से लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए नए टूल्स इस्तेमाल करने की उम्मीद

विदेशी फंड पर नए नियमों पर AIFs ने SEBI और RBI से की अपील

NSE IPO में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया समेत 5 कंपनियों के शेयर बिकेंगे

राजनाथ सिंह करेंगे 40 सुखोई जेट्स का ओवरहाल, पिछले साल के प्लान से दोगुना

ISRO का बड़ा बयान: प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, फोकस R&D और मिशन पर रहेगा

GS3 • विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति में 'अनिवार्यता की स्वीकृति' (Acceptance of Necessity) के महत्व और रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।



टेलीग्राम



वेबसाइट

हर सुबह **टेलीग्राम** पर पाएँ

रोज़ सुबह 5 बजे पीडीएफ + क्विज़ • हर रविवार साप्ताहिक • हिंदी और अंग्रेज़ी • मुफ्त, बिना साइन-अप।

t.me/satyadheesh • satyadheesh.in/upsc/reports

नोट्स सत्याधीश के समाचार फ़ीड से स्वचालित रूप से बनाए जाते हैं और यूपीएससी सीएसई पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर में उपयोग से पहले तथ्यों का मूल रिपोर्ट या पीआईबी से मिलान करें।